हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02 अंक : 67 जौनपुर, शनिवार 02 दिसम्बर 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

सीमाएं सुरक्षित नहीं होने पर कोई भी देश समृद्ध नहीं हो सकता, बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह

एजेन्सी

हजारीबाग। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के विकास में सीमा सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि, अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो वह कभी भी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश को चंद्रमा पर पहुंचाया है, जी20 सम्मेलन के साथ पूरे विश्व में देश की ध्वजा फहराई है और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचाया है। यह सब सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे बीएसएफ जैसे बलों के कारण संभव हो पाया। अमित शाह ने कहा, बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर मैं बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं... पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने

केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पिछले नौ वर्षों में भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं के लगभग 560 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई है और अंतरालों को पाट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर इन दोनों सीमाओं पर केवल 60 किलोमीटर क्षेत्र में श्कुछ छोटे–छोटे हिस्से ही बचे हैं जिन्हें पाटा जा रहा है। शाह ने कहा कि अगले दो साल में हम इन दोनों सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बना लेंगे। भारत–पाकिस्तान की 2,290 किलोमीटर लंबी सीमा और भारत–बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर जलीय, पर्वतीय और दलदली इलाके हैं और यहां बाड़ लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में बीएसएफ और अन्य एजेंसियां घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने यहां श्मेरू प्रशिक्षिण शिविर में बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, श्श्आप, बीएसएफ इस यात्रा के आवश्यक स्तंभ हैं। शाह ने कहा, श्श्मैं ऐसे मुगालते नहीं पालता कि सीमा पर अकेले बाड़ देश की रक्षा कर सकती है, यह तो केवल मदद करती है। बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान देश की सुरक्षा करते हैं। बीएसएफ की स्थापना एक दिसंबर, 1965 को की गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि जब भी देश में भाजपा की किसी सरकार ने सत्ता संभाली है, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी सरकार।उन्होंने कहा, अटल जी की सरकार ने सीमा पर एक ही बल के तैनात रहने की योजना लाई थी तो मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोड़ा। शाह ने कहा, श्श्हमने भूमि व्यापार के अलावा रेल, सड़क, जलमार्ग संपर्क और टेलीफोन संचार को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि देश माओवादियों द्वारा चलाये जा रहे सशस्त्र और हिंसक अभियान को समाप्त करने के करीब है। शाह ने कहा कि पिछले दस साल में नक्सली हिंसा की घटनाएं 52 प्रतिशत तक कम हुई हैं, इन घटनाओं में मृत्यु के मामलों में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है और प्रभावित थानों की संख्या भी 495 से घटकर 176 रह गई है। उन्होंने कहा, श्श्बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अंतिम हमले की प्रक्रिया चल रही है। हम देश में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले दस साल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 199 नए सुरक्षा बल शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, श्श्मुझे विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले दस साल के कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लड़ाई जीतने में कामयाब रहे हैं और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे हैं।

सीएम योगी ने लगाया जनता दरबारय 300 लोगों की सुनी फरियाद

एजेन्सी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे पर है। आज यानी शुक्रवार को सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम ने अपनी समस्या लेकर आए सभी फरियादियों से बातचीत की और उनकी समस्या सुनी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को समय से जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए है। सीएम ने जनता को भरोसा दिलाया कि सभी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। बता दें कि मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे।

सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार आवास व इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही न की जाए और भूमि कब्जाने वाले दबंग, माफिया पर लगाम कसने में तत्परता दिखाई जाए। जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए अधिकारी हर पीड़ित की समस्या का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

सीएम के जनता दर्शन में करीब 300 लोग पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही।

इस दौरान एक महिला ने आवास की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला को पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाए। सभी ने सीएम को अपने प्रार्थना पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने सभी के पास जाकर ध्यान से उनकी समस्या सुनी और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं, सीएम ने बच्चों से भी प्यार और दुलार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया।

कमता व चिनहट ओवरब्रिज पर अब दोनों तरफ से आ–जा सकेंगे वाहन

एजेन्सी

लखनऊ। लखनऊ से बाराबंकी–अयोध्या जाने वाले वाहन अब कमता ओवरब्रिज व चिनहट ओवरब्रिज से भी जा सकेंगे।अभी तक इन दोनों ओवरब्रिज पर एकल मार्ग व्यवस्था थी और बाराबंकी–अयोध्या से आने वाले वाहन ही इससे होकर गुजर रहे थे।दोनों ओवरब्रिज पर दोनों तरफ से आवागमन शुरू करने को लेकर जेसीपी कानून व्यवस्था ने एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा है। इस पर एनएचएआई ने भी अपनी सहमति दे दी है।ट्रायल के बाद तीन–चार दिन में व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।सही रहा तो स्थायी कर दिया जाएगा।जेसीपी उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया को प्रस्ताव भेजा था। इसमें लिखा था कि श्रीराम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस वजह से पालीटेक्निक चौराहा से कमता तिराहा से लेकर लखनऊ–बाराबंकी सीमा , इंदिरा नहर तक ट्रैफिक का दबाव लगातार बना रहता है।बाराबंकी–अयोध्या की ओर जाने वाले लोगों को चौराहे के पास

बमुश्किल दो या तीन लेन ही मिल पाती है जबकि बाराबंकी–अयोध्या से लखनऊ आने वाले लोगों को समस्या नहीं होती है क्योंकि क्योंकि वापसी में सर्विस लेन के साथ चार–पांच लेन मिल जाती है।प्रस्ताव में है कि पालीटेक्निक चौराहे से इंदिरा नहर के बीच तीन ओवरब्रिज बने हैं। इसमें दो वन वे है।इन दोनों सिंगल ओवरब्रिज पर इस समय वाहनों का आवागमन सिर्फ अयोध्या से लखनऊ की सिंगल लेन में होता है। सड़क कम मिलने की वजह से लखनऊ से अयोध्या की ओर जाने पर वाहनों की संख्या सर्विस रोड तथा ओवरब्रिज के नीचे बांयी लेन पर बहुत ज्यादा होती है।वापसी के लिये वन–वे ब्रिज पर वाहनों की संख्या कम रहती है।ऐसे में दोनों सिंगल लेन ओवर ब्रिज को डबल लेन में चलाया जाने की जरूरत है। दोनों ओवरब्रिज पर दो लेन में यातायात जरूरी होने के पीछे तर्क दिये गए हैं। लखनऊ से बाराबंकी–अयोध्या जाने वाले वाहन ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. इस वजह से चौराहों पर ब्रिज के नीचे संकरे मार्ग से इन्हें निकलना पड़ता है। इससे जाम लगता रहता है। बाराबंकी जाने वाले वाहनों को कमता और चिनहट अंडर पास से गुजरना पड़ता है।यहां हमेशा जाम लगता है। लखनऊ से बाराबंकी जाने वाले वाहन सर्विस रोड और मुख्य मार्ग के बीच में बिजली के खम्भे लगे है इससे रास्ते की चौड़ाई का इस्तेमाल चालक नहीं कर पाते हैं।पॉलीटेक्निक से बाराबंकी जाने वाले वाहनों की एक लेन शहीद पथ की ओर मुड़ जाती है और बाराबंकी की ओर जाने के लिये सिर्फ दो लेन मिल पाती है। इस पर ऑटो का कब्जा रहता है।कमता चौराहे पर अवध बस स्टेशन होने से यात्रियों ऑटो,ई–रिक्शा काफी संख्या में चौराहे पर ही खड़े रहते है।इनके बीच से बाराबंकी–अयोध्या के वाहन जाते हैं। बाराबंकी से लखनऊ आने वाले वाहन ओवरब्रिज के साथ साथ नीचे सर्विस रोड से भी गुजरते है। ओवरब्रिज का अधिकतम उपयोग तक नहीं हो पाता है।वापसी के लिये चौराहों को भी पार नहीं करता होता है। जेसीपी उपेन्द्र कुमार ने बताया कि नौ नवम्बर को व्यस्त समय में शाम और रात को चिनहट ओवरब्रिज पर आधे हिस्से को बंद कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज, राष्ट्रगान के अपमान का लगा आरोप

एजेन्सी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 11 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी द्वारा विधानसभा परिसर में दिए गए धरने के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। संसदीय मामलों के मंत्री शोभनदेव चटर्जी ने कहा कि ये शिकायतें तृणमूल कांग्रेस विधायक दल की ओर से दर्ज कराई गई हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के विधायक 29 नवंबर को राज्य के प्रति केंद्र के श्श्भेदभावपूर्ण रवैयेश्श् के खिलाफ प्रदर्शन बंद करने से पहले, बी आर आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे राष्ट्रगान गा रहे थे। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने राष्ट्रगान के दौरान भाजपा विधायकों पर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाने तथा घंटियां बजाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर गाया जा रहा था। भाजपा ने कहा कि भले ही टीएमसी विधायकों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया हो, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जो उनके विरोध स्थल से सुनाई नहीं पड़ रही थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी उसके विधायकों को मनगढंत आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा ने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं दिखाया और उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है।श्श् विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय ने भी कहा कि उनके खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय के एक सूत्र ने कहा कि हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने ने इस संबंध में 11 भाजपा विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्र ने कहा कि कथित घटना का वीडियो फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि राष्ट्रगान गाया जा रहा है। उन्होंने कहा, श्श्टीएमसी की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा विरोध जारी था और हम आंबेडकर की प्रतिमा से थोड़ी ही दूरी पर थे। अगर राष्ट्रगान गाया भी गया तो यह बहुत ही धीमी आवाज में गाया जा रहा था। क्यों? क्या वे राष्ट्रगान के बोल भूल गए थे? हमें टीएमसी से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है।

सुर्खियों में बने रहने की नेताओं की लालसा पर राहुल ने कसा तंज

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नेतृत्व सभी लाउडस्पीकर और कैमरों को अपनी दिशा में मोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन वह माइक का मुंह जनता की ओर मोड़ना पसंद करते हैं। यहां प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा पहला प्रियदर्शिनी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि नेता बड़े मजेदार किस्म के लोग होते हैं और लाउडस्पीकर हमेशा उनके सामने रहता है। गांधी ने कहा, यह (लाउडस्पीकर) भीड़ की तरफ नहीं होता क्योंकि हम खुद को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं।

वक्फ बोर्ड भर्ती मामला, दिल्ली कोर्ट ने तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

एजेन्सी

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, इसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपध्यिों जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत उनकी पहले दी गई 14 दिन की जेल की अवधि समाप्त होने पर 15 दिसंबर तक बढ़ा दी। आरोपी की ओर से पेश होते हुए, वकील नितेश राणा ने तर्क दिया कि रिमांड आवेदन पूरी तरह से ष्यांत्रिकष् है और इसमें हिरासत बढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। राणा ने कहा, आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जांच जारी है। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष, राणा ने एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुआ है, और अपराध की आय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा था, गिरफ्तारी अपने आप में अवैध है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के आदेश के खिलाफ है। योग्यता के अभाव में रिमांड आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। राणा ने दलील दी थी कि ईडी के पास उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई नया आधार नहीं है। 11 नवंबर को अदालत ने उनसे 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। ईडी की हिरासत की मांग अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को बढ़ावा देने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करने, आरोपी व्यक्तियों का एक–दूसरे और अन्य व्यक्तियों से आमना–सामना कराने और सच्चाई का पता लगाने और मिलीभगत का पता लगाने के लिए की गई थी।

दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का भरोसा

एजेन्सी

भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल के पूर्वानुमान वास्तविकता से बहुत दूर हैं। नेता ने विश्वास जताया कि सबसे पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लोग पिछले दो दशकों से भाजपा के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने बदलाव के लिए मतदान किया है। सिंह ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे अलग–अलग हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 130 से अधिक सीटें और स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा, लोग परिवर्तन चाहते हैं जिसके लिए कांग्रेस को वोट मिलेंगे। लोग शिवराज सिंह चौहान और उनके झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। गुरुवार को एग्जिट पोल जारी होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

पीयूष गोयल ने कॉरपोरेट्स से निवेश बढ़ाने का किया आग्रह

एजेन्सी

नयी दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कॉरपोरेट्स से भारत में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विकास से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ रही है। तीसरे भारत ऋण पूंजी बाजार शिखर सम्मेलन 2023–के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, गोयल ने कहारू ष्वित्तपोषण का प्रतिस्पर्धी स्रोत उन लोगों से निवेश आकर्षित कर रहा है जो अधिक सुरक्षा की तलाश में हैं। शेयर बाजार भी पहली बार 4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू रहा है और भारत बड़े अवसरों वाले शीर्ष पांच वैश्विक बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का भारी निवेश देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है और इसे गति दे रहा है। गोयल ने कॉरपोरेट जगत से भारत में निवेश करने का आग्रह किया, क्योंकि देश दुनिया के एक विश्वसनीय भागीदार और एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में बहुत उज्ज्वल भविष्य के शिखर पर खड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत आज एक अच्छी स्थिति में है जहां वह आश्वस्त हो सकता है कि आने वाले कई वर्षों तक उसे उस तरह का संकट नहीं होगा जैसा 2013 में देखा गया था। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस तिमाही में 7.6 प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। गोयल ने कहा कि एक लचीला ऋण पूंजी बाजार नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्प्रेरक होगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर शहरीकरण होगा क्योंकि टियर 2 शहर भी महानगर बनने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ रही है, इससे देश भर में खर्च करने की शक्ति बढ़ रही है। एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के क्षेत्र हमारे भविष्य को शक्ति प्रदान करेंगे।

अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव का पदभार संभाला

एजेन्सी

श्रीनगर। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के अधिकारी अटल डुल्लू ने शुक्रवार को जम्मू–कश्मीर के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्होंने ए.के. मेहता की जगह ली है जो गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए थे। नियुक्तियों जुड़ी कैबिनेट की समिति ने डुल्लू को समय से पहले एजीएमयूटी कैडर में वापस भेज दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जम्मू–कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया। डुल्लू शुक्रवार को यहां पहुंचे और सिविल सचिवालय में अधिकारियोंऔर अन्य कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने मुख्य सचिव का पदभार संभाला। वह केंद्र शासित प्रदेश के ही निवासी हैऔर जम्मू–कश्मीर के मुख्य सचिव बनने वाले तीसरे कश्मीरी पंडित हैं। उनसे पहले, पुष्कर नाथ कौल और विजय बकाया कश्मीर पंडित समुदाय के अन्य दो सदस्य थे जिन्होंने यहां मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था।

धोनी के साथ बीजेपी नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें वायरल

एजेन्सी

रांची। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर कई तरह की चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर यह सवाल तैर रहा है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसका कोई सियासी मायने है?दरअसल, महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार की शाम मुंबई की फ्लाइट पकड़ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थे। इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह एवं कांके क्षेत्र के भापा विधायक समरी लाल ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सामने आईं और देखते–देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोग इन तस्वीरों को धोनी के राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं से जोड़कर चर्चा करने लगे। राज्य सभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्क्रिकेट के कोहिनूर, झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी जी से एक अच्छी मुलाकात।

सम्पादकीय

तेजस का तेज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 नवम्बर को बेंगलुरु में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद प्रधानमंत्री ने काफी गर्व महसूस किया। जिस तेजस विमान की चर्चा फिर से शुरू हुई है उसका अपना सफरनामा काफी संघर्षपूर्ण रहा है। इस विमान को बनाने में 33 वर्ष लग गए। जिस विमान के निर्माण में लगातार बाधाएं आती रही हैं आज उसी विमान के लिए दुनिया लाइन लगाकर खड़ी है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपिन्स समेत छह देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रूचि दिखाई है। इसके अलावा अर्जेंटीना, नाइजीरिया और मिस्र को भी तेजस को निर्यात करने की सम्भावनाएं तलाशी जा रही हैं।

सबसे पहला सवाल तो शायद आपके मन में यह आ रहा होगा कि भारत ने यह विमान क्यों बनाना शुरू किया? तो इसका सीधा और आसान जवाब यह है कि पिछले पांच दशकों में 400 से ज्यादा मिग–21 विमान क्रेश हुए, जिसकी वजह भारतीय सरकार मिग–21 की जगह कोई दूसरा ऑप्शन तलाश कर रही थी जो मिग–21 से कई मायनों में बेहतर हो और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तेजस मिग–21 की जगह लेने में कामयाब हो गया। भारतीय वायु सेना में हल्के विमान शामिल करने की जद्दोजहद साल 1983 में ही हो चुकी थी। सरकार की तरफ से इसका ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस पर काम शुरू हो चुका था। उस वक्त साइंटिस्ट्स के सिर्फ दो ही मकसद थे, पहला यह कि मिग–21 की जगह एक बेहतर फाइटर जेट तैयार करना है वहीं दूसरा यह था कि जो विमान तैयार किया जा रहा है वो हल्का भी होना चाहिए, 1983 से लेकर साल 2001 तक इसके पीछे कड़ी मेहनत हुई और जनवरी 2001 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी। इस विमान को बनाने की जद्दोजहद 1983 में ही शुरू हो गई थी लेकिन एक के बाद एक मुघ्सीबतें आती रहीं। पहले 1983 में शुरू की गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोटों के चलते अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। तब दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक खेमा अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का था। प्रतिबंधों के चलते भारत को कई घ्उपकरण मिलना बंद हो गए थे। 1998 में अटल बिहारी के शासनकाल में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने इस परियोजना को लगभग रोक दिया था। क्योंकि इससे कुछ आयातित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बंद हो गई थी। इन प्रतिबंधों के चलते परियोजना दो दशक पीछे धकेल दी गई थी लेकिन धीरे–धीरे परिस्थितियां बदलीं। देशों के बीच संबंधों की नई परिभाषाएं गढ़ी गईं। 1983 से लेकर 2001 तक इसके पीछे कड़ी मेहनत हुई और 4 जनवरी 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल घबिहारी वाजपेयी ने इस विमान में पहली उड़ान भरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विमान को तेजस का नाम दिया था। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तेजस विमान को उड़ाने वाले पहले मंत्री बने। तभी उन्होंने देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय ने अब तक कुल 324 तेजस विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया। इस विमान की कई खासियतें हैं। यह विमान स्पीड का सौदागर है। तेजस को एल्युमीनियम, लीथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50 फीसदी कलपुर्जे भारत में बने हैं। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वह 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर हैं। साथ ही यह हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को एक अनोखा विमान बनाती हैं जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। इन खूबियों की वजह से इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

मोदी सरकार रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादों पर लगातार जोर दे रही है। अब भारत में ही रक्षा उपकरण के भी निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एमके–2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन का उत्पादन करने के लिए भी एचएएल के साथ समझौता हो चुका है। तेजस में समय–समय पर परिवर्तन किये जाते रहे हैं। अब इनके अपग्रेडेड वर्जन 2024 से लेकर 2028 के बीच तैयार किए जाएंगे।

तेलंगाना में भी शानदार मतदान

तेलंगाना में भी धुआंधार मतदान के बाद 3 दिसम्बर को चुनाव परिणामों का इन्तजार देश के हर नागरिक को रहेगा। देश के जिन पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम व तेलंगाना में चुनाव हुए हैं उन सभी में इस बार अच्छा मतदान हुआ है जिससे पता चलता है कि मतदाता राजनीति के प्रति लगातार सजग हो रहे हैं। तेलंगाना इन सभी राज्यों में सबसे युवा राज्य है जिसका गठन 2014 में केन्द्र की डा. मनमोहन सिंह सरकार ने किया था परन्तु इसी साल बाद में हुए विधानसभा चुनावों में यहां क्षेत्रीय नेता श्री चन्द्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जीत गई थी। इसकी वजह यह समझी गयी थी कि तेलंगाना निर्माण के लिए इस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया था और जन आन्दोलन छेड़ा था। तब से अब तक चन्द्रशेखर राव ही इस राज्य के मुख्यमन्त्री चले आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनावों में सत्ता विरोधी लहर चली है। इसमें कितना सत्य है, इसका पता तो 3 दिसम्बर को ही चलेगा परन्तु आम जनता का उत्साह चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह देखने को मिला उससे इतना तो कहा ही जा सकता है कि जनता निर्णायक फैसला कांग्रेस अथवा समिति को देने जा रही है। पिछली बार भी यहां के मतदाताओं ने राष्ट्रीय समिति के प्रत्याशियों को जबर्दस्त समर्थन दिया था और 119 सदस्यीय विधानसभा में इसके 88 सदस्य भेज दिये थे। दूसरे नम्बर पर कांग्रेस रही थी जिसके 21 सदस्य चुने गये थे जबकि भाजपा का केवल एक विधायक ही चुना गया था। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस व राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या में भारी बदलाव आ सकता है जबकि भाजपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादे मुसलमीन के बाद चौथे नम्बर पर ही रहेगी। इससे कहा जा सकता है कि असली मुकाबला कांग्रेस व राष्ट्रीय समिति के बीच ही है। तेलंगाना छोटा राज्य है मगर इसकी शहरी जन संख्या 39 प्रतिशत व ग्रामीण जनसंख्या 61 प्रतिशत के लगभग है। इसलिए जिस पार्टी का दबदबा गांवों में होगा अंत में विजयश्री उसी का वरण कर सकती है। पिछली बार राष्ट्रीय समिति को 48 प्रतिशत के लगभग मत मिले थे जबकि कांग्रेस को 32 प्रतिशत के आसपास वोट मिले थे। देखना यह होगा कि इन दोनों पार्टियों के मतों में इस बार कितना अन्तर रहता है और पलड़ा किसके पक्ष में झुकता है। जहां तक पिछली बार के मतदान का सवाल है तो शहरी क्षेत्रों में यह 50 प्रतिशत से भी कम रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से भी ऊपर रहा था जिससे औसत मतदान प्रतिशत 73 के करीब रहा था। यह राज्य भी अन्य राज्यों की तरह बता रहा है कि गांवों में रहने वाले और अनपढ़ व गरीब समझे जाने वाले लोग राजनीतिक रूप से अधिक सचेत व बुद्धिमान होते हैं। इससे सकल भारत की राजनीतिक सूझबूझ का ही पता चलता है क्योंकि असली भारत गांवों में ही रहता है। इस राज्य में 85 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुओं की है जबकि मुस्लिम 13 प्रतिशत से कुछ कम और ईसाई 1. 2 प्रतिशत हैं। असली लड़ाई में जो भी पार्टियां हैं वे अपने–अपने को किसानों व ग्रामीणों का हितैषी ही बताती हैं। चुनाव परिणाम बतायेंगे कि लोगों ने किस पार्टी को अपना हितैषी समझा है परन्तु इस बार भाजपा इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना चाहती थी। यह भी देखना होगा कि उसे इस बार कितने प्रतिशत मत मिलते हैं क्योंकि पिछले चुनावों में उसकी सीट बेशक एक थी मगर मत प्रतिशत 12 के आसपास था जबकि इन चुनावों के कुछ महीनों बाद ही हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा चार सीटें ले गई थी और इसका मत प्रतिशत भी बढ़कर 18 के आसपास हो गया था। राज्य में एक पार्टी ऐसी भी है जिसका असर केवल राजधानी के क्षेत्र हैदराबाद में ही है। हैदराबाद से विधानसभा की 20 सीटें हैं। इनमें से सात सीटें पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की इत्तेहादे मुसलमीन पार्टी को मिली थीं जबकि कांग्रेस तीन पर जीती थी और बाकी राष्ट्रीय समिति के खाते में गई थीं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि इस बार चुनाव परिणामों में बड़ा फेरबदल होता है तो हैदराबाद भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मगर चुनावी राजनीति में कभी भी कोई नियम व परंपरा से मतदाता नहीं बंधते हैं क्योंकि वे लोकतन्त्र के असली मालिक और शहंशाह होते हैं।

उनके वोट में नेताओं को अर्श से फर्श पर लाने की ताकत होती है जिसे राजनीति में बदलाव कहा जाता है। लोकतन्त्र की विशेषता यह भी होती है कि यह बदलते समय के अनुसार बदलाव मांगता रहता है और इस व्यवस्था में जनता के सामने कभी भी विकल्पों की कमी नहीं रहती क्योंकि भारत बहु राजनैतिक दल व्यवस्था का लोकतन्त्र है। अतः भारी मतदान होना भी लोकतन्त्र की जय है और 3 दिसम्बर को जब परिणाम आयेंगे तब भी केवल लोकतन्त्र ही जीतेगा।

खेल में खनकती पूंजी

अरविन्द मोहन

विश्वकप क्रिकेट में कमेंटरी करने भारत आए पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग की यह टिप्पणी अभी भी सोशल मीडिया पर चर्चा और विवाद का विषय बनी है कि आस्ट्रेलिया की फाइनल की जीत शक्रिकेट माफिया के खिलाफ न्याय की जीत है।श उनका इशारा ही नहीं, साफ कहना है कि क्रिकेट पर माफिया काबिज है, वही अधिकांश फैसले कराने लगा है और आस्ट्रेलिया ने अपने खेल के दम पर इसक्रम को पलटा है। इस बयान से उन लोगों की बाछें खिल गई हैं जो गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय क्रिकेट प्रशासन पर हावी जमात के आलोचक रहे हैं। यह आलोचना अभी से नहीं डालमिया, बिन्द्रा और पवार राज के दिनों से हो रही है और इधर यह शोर बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट प्रशासन का दबदबा बढ़ा है–निश्चित रूप से बढ़ा है, भारत की मर्जी के खिलाफ ज्यादा उल्टा फैसला होना बंद हुआ है। ऐसा भारत में क्रिकेट के बढ़ने, लोकप्रिय होने और क्रिकेट में बाजार की तरफ से भारी पैसा आने की वजह से ज्यादा हुआ है, किसी माफिया के चलते उतना नहीं। स्वयं पोंटिंग से लेकर आस्ट्रेलिया के ही नहीं, दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ियों का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को लालायित रहना इसका ही प्रमाण है। जब से यह बदलाव हुआ है तब से भारत का माफिया प्रभावी हुआ हो या नहीं, भारतीय क्रिकेट प्रशासकों का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े फैसलों पर दबदबा बना है या नहीं, लेकिन इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के क्रिकेट प्रशासकों का दबदबा खत्म जरूर हुआ है। भारत ही नहीं तीसरी दुनिया के कमजोर देशों के क्रिकेट प्रशासकों

और खिलाड़ियों को उस दबदबे के चलते क्या–क्या भुगतना पड़ा है इसका किस्सा लिखना शुरू हो तो पूरा पुराण बन जाएगा। अपने अनुकूल पिच बनाने जैसी आलोचना तो बहुत ही हल्की है। अब ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट प्रशासन बहुत लोकतान्त्रिक ढंग से चलता हो या वहां सारा कुछ पाक–साफ ही हो। इस बार ही आयोजन स्थल, मैदान, खेल के दिन से लेकर टिकट की ब्लैकमेलिंग और होटल या विमान भाड़ा तक में जो–जो हुआ उसे श्हेल्दी हैबिटश तो कदापि नहीं कहा जा सकता। खिलाड़ियों से ज्यादा क्रिकेट प्रशासकों की अय्याशी की भी चर्चा खेल के लिए स्वस्थ नहीं है। क्रिकेट के प्रसारण राइट्स की कहानी भी गंदली है और दर्शक बढ़ने का ज्यादा लाभ खिलाड़ी और प्रशासन की जगह बाजार उठाता जा रहा है। इसी का प्रमाण है कि भारत के अंदर भी नेट के जरिए मैच देखनेधदिखाने का कारोबार सामान्य टीवी प्रसारण से अलग किया गया है। तब भी वहां साढ़े पांच करोड़ तक दर्शक पहुंचे ही नहीं हैं, ज्यादा समय तक क्रिकेट देखने का रिकार्ड भी दर्ज हो रहाहै। दसियों भाषाओं में कमेंटरी हो रही है। दस सेकेंड के विज्ञापन का रेट तीस लाख रुपए तक पहुंचने की चर्चा है। एक फोटो इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्रिकेटरों के बल्ले से लेकर वर्दी तक पर कितनी कंपनियों के विज्ञापन का बोझ होता है इसकी गिनती मुश्किल हो गई है। कैमरा कहां फोकस करे इसको लेकर झगड़ा होता है। क्रिकेट दिखाने का सामान्य शिष्टाचार पीछे चला गया है। बाजार और ब्रांड के अलावा पर्सनल खुराक और ट्रेनर भी ब्रांड बनाते जा रहे हैं। कमेंटेटरों तक को मिलने वाले पैसे आंख फाड़ने वाले हैं, उपहार और अन्य सुविधाओं का तो हिसाब ही अलग है। अलबत्ता, क्रिकेट प्रसारकों को भारत के फाइनल में हारने से ही नहीं,धमाकेदार ढंग से लगातार दस मैच जीतकर फाइनल पहुंचने से भी शिकायत रही है। भारतीय गेंदबाज इस बार फाइनल के अलावा लगभग सभी मैचों में सफल रहे और पूरे पचास ओवर की जगह छब्बीस, सत्ताईस ओवर में ही विपक्षी दल को समेट देते थे। विपक्ष के कम स्कोर को धमाकेदार भारतीय बल्लेबाज पचीस–तीस ओवर में ही पूरा कर लेते थे। ऐसा प्रतियोगिता के ज्यादातर मैचों में हुआ और नजदीकी मुकाबले देखने के लिए दर्शक भी तरसे। ऐसे मुकाबलों में बाजार के लोगों को विज्ञापन के लिए कम समय मिलता है। अगर पचास ओवर की पारी चालीस ओवर से पहले निपट जाए तो 7000 से लेकर 7500 सेकेंड के विज्ञापन समय का नुकसान होता है। यह समय श्कीमतीश है और यह नुकसान बड़ा। जब विश्वकप और उससे पहले हुए एशिया कप के मुकाबलों (वैसे यह टूर्नामेंट बारिश के चलते बहुत बाधित हुआ) ने श्राद्ध–पक्ष में भी टीवी की रिकार्ड बिक्री से धमाकेदार शुरूआत करा दी थी तो बाजार की उम्मीद काफी होना स्वाभाविक है। उसने बेमौसम कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ाने का अनुभव किया तो कोल्ड ड्रिंक के नए विज्ञापन ही नहीं बढ़े, दो–तीन ब्रांड भी बहुत ध्ूम–धड़ाके से लांच कर दिए गए। इस बार स्टेडियम ही नहीं सड़कों पर भी भारतीय जर्सी का रंग छाया रहा, पर उससे ज्यादा सड़क के किनारे सस्ते ब्रांड और आनलाइन बिक्री में ब्रांडेड माल की धूम रही। देश में सौ करोड़ की एक ब्रांड की जर्सी बिकने का अंदाजा है। आनलाइन बुकिंग में आठ–नौ गुना तक ज्यादा मांग आई है, पर कहना होगा कि फाइनल की हार ने इस धूम–धड़ाके पर रोक ही नहीं लगाई, इसकी चर्चा भी बंद करा दी है।

इन ब्रांडों से ज्यादा नुकसान क्रिकेट को यहां तक पहुंचाने वाले खिलाड़ियों की कमाई में हो गया लगता है। जिस विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बल्ले से धूम मचाई, उनका ब्रांड मूल्य या विज्ञापनों की संख्या में ज्यादा वृद्धि का अनुमान नहीं है। यह तब है जब विराट ने अपनी पुरानी मार्केटिंग कंपनी से करार तोड़कर नई कंपनी से करार किया था जिससे नए रेट पाने में आसानी होगी। वैसे अकेले उनकी ही कमाई डेढ़ हजार करोड़ के करीब है। बाकी तो इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा धूम मचाने वाले मोहम्मद समी को अभी तक कोई बड़ा ब्रांड नहीं मिला है और बाजार के जानकार मानते हैं कि उनको ज्यादा ब्रांड ही नहीं, ज्यादा रेट मिलने की भी उम्मीद नहीं है। उनको पहले 40 से 50 लाख रुपए प्रति ब्रांड मिलता था जो अब एक करोड़ तक पहुंच सकता है, जबकि बड़े खिलाड़ी और सिनेस्टार दस करोड़ तक पाते हैं। अब पोंटिंग को भारतीय क्रिकेट प्रशासकों पर टिप्पणी करने की सूझी, लेकिन उनको बाजार का यह खेल, यह दादागिरी, यह माफियागिरी समझ आती भी है या नहीं यह कहना कठिन है। वे इससे कहां अलग हैं, यह समझना तो और भी मुश्किल है।

खनिज तेल आपूर्ति में कटौती का सवाल, सभी निगाहें ओपेक की बैठक पर

के रवीन्द्रन

तेल बाजार इस सप्ताह आगामी ओपेक् बैठक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जिसकी 26 नवम्बर की बैठक को आंतरिक समस्याओं के कारण स्थगित करना पड़ा था। यह बैठक उत्पादक और आयातक दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इस आकलन के बीच कि एक नये उत्पादन में कटौती पर समझौता चुनौतीपूर्ण होने वाला है? हालांकि ओपेक की बैठकें पहले भी स्थगित की जा चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार है कि यह स्थगन इतने दिनों तक चला है। स्थगन के कारण ही कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। सप्ताह की शुरुआत में क्रूड की कीमतें लगभग 74.70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही थीं, जबकि ब्रेंट क्रूड गिरकर लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। मामूली वृद्धि दर्ज करने के बाद, सप्ताहों में इस तरह की पहली बढ़ोतरी, ओपेक् द्वारा अफ्रीकी देशों में उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्री स्तरीय बैठक को 30 नवंबर तक स्थगित करने के बाद सप्ताह के मध्य में कीमतों में गिरावट आई। यह स्थगन ओपेक् समूह के भीतर उत्पादन में कटौती के समझौते पर पहुंचने में कठिनाइयों का संकेत देता है। प्रत्येक सदस्य देश 2024 में कीमतों का समर्थन करने के लिए उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है, लेकिन सवाल यह है कि आपूर्ति में कटौती का बोझ कैसे साझा किया जाये। यह माना जाता है कि आगे की कटौती के बिना, कीमतें 2024 तक 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहेंगी। जून 2023 में तय किये गये 2024 उत्पादन कोटा में 23 सदस्य देशों में से नौ के लिए कम उत्पादन लक्ष्य शामिल था, जो रूस, नाइजीरिया, अंगोला, मलेशिया, अजरबैजान, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, ब्रुनेई और सूडान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन देशों के लिए कम उत्पादन कोटा स्वीकार करना भी मुश्किल होगा। हालांकि, चुनौतियों के बावजूद, तेल बाजार विशेषज्ञ रिस्टैड एनर्जी को उम्मीद है कि ओपेक् आगामी बैठक में उत्पादन कम करने के समझौते पर पहुंचेगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक जैसे सदस्यों से आगे स्वैच्छिक कटौती शामिल हो सकती है। वहीं, रिस्टैड गतिरोध की संभावना से इनकार करने को तैयार नहीं हैं। इस बात को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि सरगना सऊदी अरब प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल (बीपीडी) की स्वैच्छिक कच्चे तेल उत्पादन में कटौती पर क्या निर्णय लेता है। चाहे वे कोई भी रास्ता अपनाएं, उत्पादन में कटौती पर सऊदी अरब का निर्णय अंततरू वैश्विक तेल कीमतों के अल्पकालिक भविष्य को आकार देगा।

राज्य आपूर्ति को सीमित करके कीमतें ऊंची रखने की इच्छा को इस ज्ञान के साथ संतुलित कर रहा है कि ऐसा करने से समग्र बाजार हिस्सेदारी में और गिरावट आयेगी।

हाल की कीमत में गिरावट इस बात का संकेतक हो सकती है कि ओपेक बैठक में क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सऊदी ने बार–बार प्रदर्शित किया है कि उनका मूल्य स्तर 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है। सऊदी अरब ने उस बैठक के मौके पर अपनी स्वैच्छिक कटौती की घोषणा की, शुरुआत में जुलाई के लिए 1 मिलियन–बीपीडी उत्पादन कटौती की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद इसे मासिक आधार पर अगस्त और सितंबर तक बढ़ा दिया गया, जबकि सितंबर की शुरुआत में, रियाद ने इस साल के अंत तक विस्तार की घोषणा की। तेल बाजार यह देखना चाहेंगे कि क्या सऊदी अरब इन कटौती को 2024 तक बढ़ाता है या वह इन्हें धीरे–धीरे कम करना चाहता है या इस साल के अंत में इन्हें समाप्त होने देता है। चाहे जो भी हो, सऊदी अरब के फैसले का तेल बाजारों और विशेष रूप से अगले साल तेल की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

रिस्टैड एनर्जी का मानना है कि सऊदी स्वैच्छिक कटौती को 2024 तक नहीं बढ़ाया जायेगा, क्योंकि आपूर्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जो अगले साल की पहली तिमाही के लिए संतुलित बाजार का संकेत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी तिमाही में 600,000 बीपीडी से अधिक का बाजार अधिशेष दिखाई दे रहा है।

आगे बढ़ते हुए, अगले वर्ष की दूसरी छमाही में लगभग 450,000 बीपीडी की कमी होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, रिस्टैड को उम्मीद है कि इस साल लगभग 1. 2 मिलियन के महत्वपूर्ण घाटे की तुलना में 2024 में तेल बाजार काफी संतुलित रहेगा। हाल के सप्ताहों में तेल की कीमत पर गिरावट का दबाव बढ़ गया है, अत्यधिक आपूर्ति की चिंताओं के कारण भारी बिकवाली के कारण कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं। यह अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुए इजराइल–हमास संघर्ष के फैलने के ठीक बाद तेल की कीमत के स्तर से काफी नीचे है, जब कीमतें लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। मंदी की उम्मीदों को और अधिक बल दे रहे हैं, हाल के आंकड़े, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी वाणिज्यिक कच्चे माल की सूची पिछले चार हफ्तों में बढ़ी है और अब यह 440 मिलियन बैरल है, जो एक महीने पहले 420 मिलियन बैरल से अधिक था।

रिस्टैड विश्लेषण से पता चलता है कि, ऐसे परिदृश्य में जहां सऊदी अरब स्वैच्छिक कटौती का विस्तार नहीं करता है, बाजार में मंदी बढ़ेगी और अगले साल तेल की कीमत औसतन 80 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर होगी। दूसरे छोर पर, यदि सऊदी अरब अप्रैल 2024 तक स्वैच्छिक कटौती बढ़ाता है और फिर धीरे–धीरे उन्हें कम करता है, तो 2024 में कीमत औसतन 96 डॉलर प्रति बैरल होगी। आईएमएफ का नवीनतम अनुमान सऊदी तेल के लिए 86 डॉलर प्रति बैरल की ब्रेकईवन कीमत का सुझाव देता है। इसका मतलब यह होगा कि सऊदी अरब को उस मूल्य स्तर को हासिल करने के लिए, कम से कम जून 2024 तक बाजार हिस्सेदारी देना जारी रखना होगा।

मौतों वाली कार्य संस्कृति

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ताजा रिपोर्ट बतलाती है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी बहुत खराब हालात में काम करती है। स्थितियां इतनी बुरी हैं कि उनके कारण लाखों श्रमिक और कर्मचारी किसी न किसी वजह से दम तोड़ देते हैं, फिर वह चाहे काम का बोझ हो या कार्य स्थलों पर होता प्रदूषण। यह एक तरह से क्रूर पूंजीवाद के उसी चेहरे का प्रतिबिम्ब है जो मुनाफा कमाने के लिये अमानवीयता की तमाम सरहदें लांघता है। पिछले कुछ अरसे से पूंजी के मुकाबले श्रम की घटती महत्ता का भी यह साक्ष्य है।

आईएलओ की इस 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक काम से सम्बन्धित दुर्घटनाओं और विभिन्न तरह की बीमारियों के चलते विश्व में 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। यह आंकड़ा साल 2000 के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा तथा 2015 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है जो यह बतलाने के लिये पर्याप्त है कि लोगों का मरना बदस्तूर जारी है। जो तथ्य प्रमुखता से सामने आया वह यह है कि मौतों का सबसे बड़ा कारण है प्रति सप्ताह 55 घंटों से अधिक समय तक की काम की अवधि का होना। अकेले इसी कारण से करीब 7.5 लाख कर्मचारियों व श्रमिकों ने प्राण खोये। ऐसे में इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के उस बयान का भी स्मरण हो आता है जिन्होंने हाल ही में एक चर्चा के दौरान कहा था कि श्अगर भारत को चीन से मुकाबला करना है तो यहां के प्रत्येक युवा को सप्ताह में कम से कम 60 घंटे काम करना चाहिये। दुनिया जब 55 घंटे से अधिक अवधि तक काम करने का नतीजा बड़ी संख्या में लोगों की मौत के रूप में देख रही है, तो नारायण मूर्ति का यह बयान निष्ठुर ही कहा जा सकता है। यह पूंजीवाद का वह विद्रूप पक्ष है जिसमें कारोबारियों को लोगों की जान की परवाह नहीं होती और वे आर्थिक लाभ को ही तरजीह देते हैं। ये वे मौतें हैं जिनकी रिपोर्ट हुई है या जानकारियां दस्तावेजों तक पहुंच सकी हैं। बड़ी संख्या में ऐसे गैर–संगठित क्षेत्र के लोग हैं जो जान तो गंवाते हैं परन्तु वे घोषित आंकड़ों के हिस्से नहीं बन पाते। यह पूरी दुनिया का हाल है, लेकिन तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों में श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय व चिंतनीय है जो 21वीं सदी में हासिल की गई वैज्ञानिकता, तकनीकी विकास एवं आधुनिक प्रबंधन शैली के भी विपरीत है। एशियाई, अफ्रीकी एवं लातिन अमेरिका के कई अविकसित व विकासशील देशों में लोगों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ये मौतें व्यापक पैमाने पर मानवाधिकार की दुर्दशा को भी बयान करती हैं। वर्गीकृत मौतों के अलावा सोचे–समझे बिना थोपे जाने वाले सरकारी निर्णयों के कारण भी बड़ी संख्या में कार्य स्थलों पर मौतें होती हैं। भारत में नोटबंदी एक ऐसा ही उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सनक व अदूरदर्शिता से उपजे इस फैसले का नतीजा देश ने बैंकों के बाहर लोगों की तथा बैंकों के भीतर कर्मचारियों की मौतों के रूप में देखा था। इसी प्रकार कोरोना काल में भी लोगों से लिये जा रहे काम के दौरान भी हजारों लोगों ने जानें गंवाई थीं। उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान स्थानीय निकायों के चुनाव कराये गये थे। नौकरी खोने के डर से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों ने दूर–दराज जाकर चुनावी ड्यूटी की थी। पर्याप्त ऐहतियात बरतने की सुविधा न होने और इलाज की अनुपलब्धता के कारण बड़ी तादाद में मौतें हुई थीं।

आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अन्य कारण तथा उनसे मरने वाले लोगों की संख्याएं इस प्रकार हैं– गैस रिसाव व आगजनी से 4.5 लाख, काम के दौरान घायल होकर 3.63 लाख, एसबेस्टस 2.09 लाख, सिलिका 42 हजार से ज्यादा, कार्य जनित अस्थमा लगभग 30 हजार, विकिरण 18 हजार, डीजल इंजिन एग्जास्ट 14700, अर्सेनिक 7600 एवं निकल से 7300। जो सेक्टर सर्वाधिक खतरनाक माने गये हैं और जिनमें सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं, उनमें खनन, विनिर्माण, बिजली तथा प्राकृतिक गैस हैं। इस रिपोर्ट पर सिडनी में चल रही 23वीं कांग्रेस में चर्चा होगी जिसमें सुरक्षित कार्य पद्धति विकसित करने सम्बन्धी उपाय सुझाए जायेंगे। काम के दौरान घायल होने वालों की संख्या तो करोड़ों में है जो यह बतलाता है कि कामकाजी जनता के लिये सुरक्षित कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब भोपाल गैस त्रासदी के करीब 40 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 व 3 दिसम्बर, 1984 की मध्य रात्रि को यहां स्थित यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से 45 टन मिथाइल आईसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इससे 15 से 20 हजार लोग मारे गये थे और करीब 6 लाख लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। इनमें बड़ी तादाद में सामान्य जनता के अलावा संयंत्र के कर्मचारी थे जो या तो कार्यरत थे अथवा आसपास ही रहते थे। बेशक मरने वाले गैर कर्मचारी अधिक हैं परन्तु यह बतलाने के लिये ये आंकड़े पर्याप्त हैं कि कर्मचारियों को किन हालात में काम करना पड़ता है। इस त्रासदी को अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा के रूप में निरूपित किया जाता है। कारखानेदारों की औद्योगिक सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण पर खर्च न करने की प्रवृत्ति से काम करने वालों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। शासकीय विभाग एवं नियामक एजेंसियां भी इस ओर ध्यान नहीं देतीं। संवेदनहीन सरकारी मशीनरी व सरकारें सर्वहारा की बजाये पूंजीपतियों की पक्षधर होती हैं जिसका परिणाम यह मौतों वाली कार्य संस्कृति है।

डी०एल०एड०प्रशिक्षुओं का स्वागत एवं NeTT के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। डी०एल०एड० सत्र 2023–25 का स्वागत एवं छमज्ज (छमबमेंतल ज्मंबीमत ज्तंपदपदह) उन्मुखीकरण कार्यक्रम – दिनांक 1 दिसंबर 2023 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट जौनपुर) के ऑडिटोरियम हॉल मे डी० एल० एड० सत्र 2023–25 के प्रशिक्षुओं का स्वागत एवं छमज्ज कार्यक्रम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डायट के उपशिक्षा निदेशक ६ प्राचार्य डॉ० विनोद कुमार शर्मा एवं वरिष्ट प्रवक्ता डॉ० रवीन्द्रनाथ द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ प्रशिक्षुओं द्वारा नव आगंतुक प्रशिक्षुओं का स्वागत व सम्मान उनका तिलक करके किया गया । कार्यक्रम मे डायट के प्रशिक्षुओं द्वारा सभी का स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत किया गया । डायट प्रवक्ता नीरजमणि तिवारी ने डायट की कार्यप्रणाली एवं एचपीपीआई के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में उपशिक्षा निदेशक ६ प्राचार्य डॉ० विनोद कुमार शर्मा ने नवागंतु प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हुए स्व अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तम आचरण और कठिन परिश्रम के संबंध मे बताया साथ ही साथ हुमाना संस्था के बारे मे विस्तार से बताया और प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं दी। डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ रवीन्द्रनाथ द्वारा डी० एल० एड० के पाठ्यक्रम के साथ–साथ स्वानुशासन मे रहने का संदेश दिये। इस कार्यक्रम मे प्रशिक्षुओं के परिचयात्मक गतिविधि का आयोजन डायट प्रवक्ता श्री विनय कुमार यादव, श्री अमित कुमार, श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, श्री राजकुमार श्री मती मंजुलता यादव, श्री नवीन सिंह, श्री वरुण यादव, श्री रणधीर रंजन के द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम मे डायट जौनपुर मे कार्य कर रही संस्था हुमाना पीपुल टु पीपुल इंडिया के संदर्भ मे टीचर एजुकेटर श्री समय सिंह यादव द्वारा हुमाना पीपुल टु पीपुल इंडिया संस्था के इतिहास और संस्था की रूपरेखा के विषय मे बताया गया एवं हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के टीम लीडर डॉ० चंद्रशेखर द्वारा छमज्ज कार्यक्रम क्या है, वह किस प्रकार प्रशिक्षुओं के लिए लाभदायक और उपयोगी है । इसके विषय मे बताया गया ।

इस कार्यक्रम का आयोजन उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य डॉ० विनोद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन मे किया गया। कार्यक्रम का संचालन कोर ग्रुप टीचर श्री ब्रजबंधु ने किया। इस कार्यक्रम में डाइट के प्रवक्ता व सभी कर्मचारीगण एवं हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के सभी सदस्य शामिल थे।

दिव्यांगजनो का नाम मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु जागरुकता

दिव्यांगजनो को वोटर बनाने के लिए निकली दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिलाधिकारीधजिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा के नेतृत्व में चल रहे स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए स्थान रचना विशेष विधालय से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अधिकांश दिव्यांग लोग मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखे बैनर, तख्ती लिए चल रहे हैं। कुछ लोग ट्राईसाईकिल से भी चल रहे थे और लोगों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। रैली गुरुद्वारा, रासमण्डल, चौक शाही किला, अटाला मस्जिद, राजा बाजार होतें हुए पुनः रचना विशेष विधालय में पहुंचकर समपन्न हुई। इस अवसर पर स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों का नाम मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जागरुक किया जा रहा है। अभिभावक सभी पात्र दिव्यांगजनों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराये।

ताकि कोई भी पात्र दिव्यांग वोटर बनने से वंचित न रह पाये। 9 दिसम्बर तक मतदाता बनने का कार्यक्रम चलेगा। तथा रविवार 3 दिसम्बर को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बैठकर दावे व आपत्ति प्राप्त करेगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि उनके जानने में कोई भी 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग का नाम वोटर लिस्ट में नहीं दर्ज हैं तो नाम दर्ज कराये।

इस अवसर पर प्रबंधक नसीम अख्तर, दिव्यांग स्वीप नोडल संतोष कुमार सिंह, गौतम चंद्र, रवि रंजन जीतेन्द्र कुमार, सै गुलाम अब्बास जैदी, सचिन यादव, दामिनी, नीतू यादव सहित रचना विशेष विधालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथों का किया निरक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर– जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा बूथ संख्या 207 में फार्म कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएलओ और सुपरवाइजर को नए फॉर्म बढ़ाने के निर्देश दिए। सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज सबरहद में बने बूथ संख्या 233, 234, 235, 236 का निरीक्षण किया और बूथ संख्या 236 एवं 234 में सर्व कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में महिला मतदाता एवं 18–19 वर्ष से ऊपर के युवाओंध्युवतियों मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने का कार्य करें। सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहगंज (भादी) में बने बूथ संख्या 204, 205, 206, 207, 208 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वे सूची की समीक्षा करें और जिन जिन का फॉर्म नहीं आया है फार्म प्राप्त कर उसे अपलोड कराए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहगंज (भादी) में कक्षा सात के बच्चों से विज्ञान के प्रश्न पूछे और अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज सबरहद में उन्होंने बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर मिड डे मील सहित आने की जानकारी ली। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शाहगंज सहित अन्य सभी बीएलओ उपस्थित रहे।

वरदान चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 03दिसम्बर को होने वाले सामूहिक विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण : अरुणेश बाजपेई

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना)। वरदान चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 03दिसम्बर को होने वाले सामूहिक विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है ये बातें वरदान चौरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी ने कही, उन्होंने यह भी बताया कि मेरे पिता पुण्यात्मा अमिय कृष्ण चतुर्वेदी ने प्रति वर्ष 51 कन्याओ का विवाह का संकल्प वर्ष 2001 में लिया था तब से लेकर 2021 तक लगातार 51 कन्याओं का विवाह वरदान चेरिटेबल ट्रस्ट कराता चला आ रहा है। वर्ष 2022 में 40 कन्याओं का विवाह स्थानीय घण्टाघर में सम्पन्न हुये थे शेष विवाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मेरी बहन के द्वारा सुकुमा में सम्पन्न हुए । इस वर्ष भी उड़ीसा के महासमुंद अथवा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामूहिक विवाहप्रस्तावित है। यहां तक कोरोना काल मे भी आंशिक रूप से 5 कन्याओं का विवाह कोरोना के नियमो का पालन करते हुये सम्पन् हुये थे।

ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी अरुणेश बाजपेयी ने बताया कि 17 विवाह गायत्री परिवार के अतुल कपूर और उनकी टीम द्वारा सम्पन्न कराए जाएंगे और मुस्लिमों के निकाह शहर काजी के निर्देशन में करीमुद्दीन के सहयोग से सम्पन्न होंगे।

इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी,अविनाश चन्द्र गुप्ता, करुणा शंकर द्विवेदी व सहयोगी अनिल श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला, अविनाश मिश्रा, कमला, सुनीता,सरिता आदि उपस्थित रहे।

रामायण मेला समिति के द्वारा प्रथम पोस्टर का अनावरण म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं द्वितीय पोस्टर का अनावरण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवम जनरल वी. के. सिंह ने संयुक्त रूप से अयोध्या में किया

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या में परंपरागत तरीके से होने वाले 42 वें रामायण मेले के प्रथम पोस्टर (आवरण छवि) का आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलो द्वारा एवं द्वितीय पोस्टर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवम केंद्रीय मंत्री जनरल वी. के. सिंह के कर कमलों द्वारा सरयू अतिथि गृह अयोध्या में अनावरण किया गया, प्रथम पोस्टर में रामायण मेला में होने वाले कार्यक्रम के क्रम में धनुष यज्ञ की एवम द्वितीय पोस्टर में जनक जी के द्वारा कन्यादान की लीला को दर्शाया गया है । आवरण छवि में भारतीय लोक कला पर आधारित अवध की लोककला को प्रदर्शित किया गया है जिसमें अवधी लोक कला और परंपरा की झलक स्पष्ट दिख रही है,आवरण छवि लोकार्पण के माध्यम से रामायण मेला में भारतीय लोक कला एवम संस्कृति को दर्शाना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण मेला समिति के द्वारा अयोध्या की गरिमा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है । मांडवी सिंह, कुलपति, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ ने बताया कि रामायण मेले के माध्यम से स्थानीय रामलीलाओं के स्तर को वैश्विक रूप दिया जाएगा वहीं महंत गिरीश पति त्रिपाठी महापौर अयोध्या ने कहा कि रामायण मेले को विश्व स्तरीय बनाने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा आगामी रामायण मेला 14 से 19 दिसंबर 2023 का शुभारंभ करने हेतु मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया । रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष मिश्रा, जनसंपर्क अधिकारी , डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ने बताया की रामायण मेले की गरिमा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ।आवरण छवि को भित्ति फलक पर उकेरने का कार्य रीमा सिंह (शिक्षिका ,अवध विश्वविद्यालय) ने किया। 42 वें रामायण मेला के प्रथम एवं द्वितीय पोस्टर के अनावरण में महंत गिरीश पति त्रिपाठी ,महापौर, अयोध्या मांडवी सिंह ,कुलपति ,भातखंडे संस्कृति, विश्वविद्यालय, लखनऊ अयोध्या,रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष कुमार मिश्रा जनसंपर्क अधिकारी डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय रीमा सिंह, शिक्षिका, अवध विश्वविद्यालय की उपस्थिति में सरयू अतिथि गृह अयोध्या में किया गया।

शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी- आचार्य शान्तनु

जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल में संस्कार शाला का हुआ आयोजन

विशेष संवाददाता जय प्रकाश तिवारी

सुजानगंज जौनपुर। बच्चों में शिक्षा के साथ ही संस्कारों का भी बीजारोपण होना चाहिए। संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है। आज के इस भौतिक युग में संस्कार शाला का संचालन होना अत्यंत आवश्यक है।उक्त बातें मुख्य अतिथि परमपूज्य शान्तनु जी

महाराज ने संस्कार शाला में आयोजित विद्यार्थी संवाद में कही। शान्तनु जी ने कहा कि बच्चों में नैतिक शिक्षा डालने का जो कार्य शुरू किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। आज के इस बदलते परिवेश में समय निकालकर बच्चों को संस्कारवान बनाना यज्ञ करने के समान है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आदर्श समाज की स्थापना संस्कार से ही शुरू हो सकती है और संस्कार जन्म से ही डाला जा सकता है। शान्तनु जी ने कहा कि शिक्षा से पहले संस्कार की आवश्यकता है। बच्चों को घरों से ही संस्कार देना शुरू कीजिए। बच्चे के बड़े होने पर संस्कार देना मुश्किल हो जाता है इसलिए बाल्यावस्था से ही संस्कार का बीज बोना अति आवश्यक है। संस्कारशाला को नई पीढ़ी में नई चेतना प्रदान करने की दिशा बताया।इस दौरान विद्यार्थी संवाद में छात्रों की समस्याओं का भी निराकरण किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में विद्यालय के प्रबन्धक डॉ जय प्रकाश तिवारी एवं आचार्य शान्तनु जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन किया। अतिथियों का स्वागत भाषण विद्यालय की प्रधानाचार्या निशा किरण उपाध्याय ने किया। आभार ज्ञापन विद्यालय के निदेशक डॉ0 विनय कुमार त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर लाल बिहारी तिवारी, शिवानन्द चतुर्वेदी, जितेंद्र सिंह, के0पी0 सिंह, प्रीति सिंह, श्वेता सिंह सहित समस्त अध्यापक, छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

पाकिस्तान से आए वस्त्र पहनेंगे रामलला, सिंधियों ने भेजी पोशाक

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं इसी बीच पाकिस्तान से भगवान राम का वस्त्र अयोध्या पहुंच गया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये पोशाक सिंधियों ने भेजी है जिसे प्रभु राम धारण करेंगे अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है 22 जनवरी को मंदिर में रामलला और अन्य देवी देवताओं के प्राण–प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है ऐसे में रामलला की पोशाक पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अयोध्या पहुंची है रामलला की पोशाक अयोध्या के सिंधी कॉलोनी स्थित रामनगर पहुंची रामनगर के देवालय मंदिर में रामलला के पोशाक की पूजा की गई 21 पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार वस्त्र को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सिंधी समुदाय के सैकड़ों लोग रामलला की पोशाक को राम लला के मुख्य अर्चक को सौंपेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को है बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी काफी बड़े स्तर पर चल रही है 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर यूपी के सभी प्रतिष्ठित मंदिर श्राममयश होंगे पूरे प्रदेश में राज्य सरकार रामायण–रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी इसके लिए हर जिले के श्पर्यटन और संस्कृति परिषदश के जरिए स्थानीय कलाकारों और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होने वाले इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग पैसे की व्यवस्था करेगा हालांकि, इसके लिए अभी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस

अयोध्या (क्राइम रिपोर्टर) मुकेश कुमार।इनायत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगीशपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने चिकित्सक की सूचना पर युवती के शव का पंचायत नामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दे कि इनायत नगर थाना के मुंगीशपुर गांव निवासी नर्सिंग की 22 वर्षीय बेटी साक्षी सिंह का शुक्रवार की शाम को आवासीय छप्पर की बल्ली से फंदे से लटकता शव मिला है। परिजनों द्वारा पुलिस को बगैर सूचना दिए ही बेटी के शव को फंदे से नीचे उतार कर इलाज के लिए सीएचसी मिल्कीपुर पहुंचाया। जहां मौजूद डॉ जेपी विश्वकर्मा ने युवती को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह ने बताया चिकित्सक की सूचना पर सीएचसी मिल्कीपुर पुलिस टीम पहुंच कर युवती के शव को पंचायत नामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जांच–पड़ताल शुरू कर दी गई है।

कैंसर उपचार में उपयोगी है जिलेटर्स : डॉ. नितिन श्रीवास्तव

ड्रग डिलीवरी में महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट आधारित जिलेटर्स

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिकीय विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा कार्बोहाइड्रेट आधारित जिलेटर्स विषयक आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान में मुख्य वक्ता एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. नितिन श्रीवास्तव ने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जिलेटॅस का कैंसर के उपचार में विभिन्न उपयोगों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कुछ जिलेटॅस का प्रयोग करके शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए, बिना कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। डॉ नितिन ने छात्रों को जिलेटॅस का प्रयोग करके विभिन्न गंभीर बीमारियों के पहचान की विधियों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जिलेटर्स का उपयोग शरीर के अंदर ड्रग डिलीवरी में भी किया जाता है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ प्रमोद कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग निरंतर छात्रों के शैक्षणिक विकास लिए इस प्रकार के आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रज्जू भैया संस्थान के निदेशक डॉ प्रमोद कुमार यादव ने किया। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवराज सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन एमएसी के छात्र मंजीत गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मिथिलेश यादव ने किया। इस अवसर रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह, डॉ नितेश जायसवाल, डॉ दिनेश वर्मा, डॉ विजय शंकर पांडेय सहित विभाग के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे।

तीन माह नहीं चलेंगी चार जोड़ी ट्रेन

लखनऊ (संवाददाता) । जिले के होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की चार जोड़ी ट्रेनों का संचालन अगले तीन माह नहीं किया जाएगा। इनका संचालन शुक्रवार और शनिवार से निरस्त किया जाएगा। यह ट्रेनें मार्च में पटरी पर लौटेंगी। इसके साथ काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को सिर्फ हफ्ते में तीन दिन चलाया जाएगा। रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय कोहरे के चलते लिया है। जिले के यात्रियों के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस काफी महत्वपूर्ण ट्रेन है। यह रेलगाड़ी चंडीगढ़ और प्रयागराज के बीच प्रतिदिन संचालित की जाती है। इसका संचालन चंडीगढ़ से एक दिसंबर और प्रयागराज से दो दिसंबर से एक मार्च तक रद्द रहेगा। बरेली और प्रयागराज के बीच प्रतिदिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी तीन महीने निरस्त रहेगी।

कोहरे के चलते 24 ट्रेनें फरवरी तक हुईं निरस्त

लखनऊ (संवाददाता) । कोहरे के चलते डबलडेकर, हमसफर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 29 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 12583/84 लखनऊ जं. आनन्दविहार टर्मिनल डबलडेकर एक्सप्रेस 29 फरवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं, सात दिसंबर से 29 फरवरी तक 15621 कामाख्या आनंदविहार टर्मिनल, आठ दिसंबर से एक मार्च तक 15622 आनंदविहार टर्मिनल कामाख्या, सात दिसंबर से 29 फरवरी तक 14673 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस व पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक 14674 अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

सरस्वती डेंटल कॉलेज का रजत जयंती माह शुरू

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सरस्वती डेंटल कॉलेज एवं लखनऊ ने अपने 25 वर्ष पूरे होने पर 1 दिसंबर 2023 को एक महीने तक चलने वाले समारोह का अन्तिम चरण शुरू किया।

तिवारी गंज अयोध्या रोड स्थित नैक "ए" मान्यता प्राप्त और शीर्ष रैंक वाले डेंटल कॉलेज परिसर में आज एक रंगीन, आंनदमय माहौल देखा।

हारमानी बैंड के शानदार प्रर्दशन के साथ कॉलेज उत्सव "इनारा" की शुरूआत हुई जिसमें छात्र लोकप्रिय बॉलीवुड गानों पर उत्साह से नृत्य कर रहें थे पूरे परिसर को रंग–बिरंगें झंडों से साइनिज और होर्डिंगस से पूरी तरह से सजाया गया था। सभी संकाय सदस्य और छात्र हाऊस टी–शर्ट पहने हुए थे।

उद्घाघाटन समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष डा0 रजत माथुर, निदेशक, सरस्वती हॉस्पिटल, मिसेज स्मिता माथुर, का प्रधानाचार्य डा. के. एन. दुबे और कार्यक्रमों के आयोजकों ने स्वागत किया। रंग–बिरंगें गुब्बारें उड़ाकर कार्यक्रम की शुरूआत की घोषणा की गई इसके बाद छात्रों द्वारा पारंपरिक द्वीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद बीडीएस प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्राओं द्वारा विभिन्न लोकप्रिय गीतों पर उद्घाघाटन नृत्य का उत्कृष्ट प्रर्दशन किया गया । इसके बाद पूरे पूरे संकाय के लिए सुई–धागा दौड, नीबू दौड, तीन पैरों वाली दौड, पुस्तक दौड और गुब्बारें उडानें जैसी मनोंरजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सभी खेल हंसी मजाक से भरपूर थे जिसमें प्रिंसिपल डा. के एन. दुबे, डा. रागिनी और कमांडर सुमित घोष के नेतृत्व में ब्लू टीम ने मेगा इवेंट जीता। इसके बाद जोश के भरे माहौल में दो सकांय टीम के बीच रस्सा–कस्सी प्रतियोगिता आयोजित की गई। डा. सौम्या नवित एवं डा. हिमांशू के नेतृत्व वाली टीम ने शानदार जीत हासिल की। कई छात्रों ने गुप–चुप तरीकें से खीचतान में योगदान दिया। सकांय के बीच ओपन पेंटिग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें डा. आकांक्षा दुबें , डा. विवेक बैंस एवं डा. शेफाली ने जीती हासिल की। छात्र वर्ग में अंजली , अंशिका और कनूप्रिया ने पुरुस्कार जीते और श्री दिपेश माथुर को गैर संकाय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। विजेतों का प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किये गए।

सिल्वर जुबली कॉफी टेबल बुक के सर्वश्रेष्ठ विषय के लिए पुस्तक और पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता को डा. रजत माथुर, श्रीमती स्मिता माथुर, प्रिसिंपल डा. के. एन. दुबे और कमांडर सुमित घोष ने जज किया। बहुप्रतीक्षित मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच भी सरस्वती वॉरियर्स (एसडीसी) और सरस्वती किंग्स (एसएचआरसी) के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें वॉरियर्स ने 23 रन से जीत हासिल की। श्री दिपेश माथुर सर्वोच्च स्कोरर थे।

डा. रजत माथुर, कमांडर सुमित घोष, डा. देवेन्द्र चोपडा डा. सुनिरा चन्द्रा और ए.के. श्रीवास्तव के गीतों ने बैंड के प्रर्दशन को दूसरे स्तर पर पहुचा दिया। छात्र समूह खुशी से गा रहा था और पैर थिरकाने वाले धुनों पर नाच रहा था।

प्रबन्धन ने उत्कृष्ट उद्घाघाटन समारोह और इसके कार्यक्रमों के लिए आयोजकों डा. अल्का यदु, डा. कुणाल शाह, डा. सुलेमान अब्बास खान, डा. श्वेता सिंह, डा. आशीष चौहान को धन्यवाद दिया। छात्र आयोजक मे मानसी बिस्ट , राम स्वरूप, माधव, महिमा, अक्षत तिवारी के मेहनत की भी सहारना की गई। 5 घटों का भव्य कार्यक्रम बैंड एवं नाच गाने के साथ समाप्त हुआ।

सस्थान इस पूरे महीने अपने रजत जंयती समारोह के हिस्से के रूप में उत्सव और प्रतिस्पर्धी खेल, साहित्यक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन करेगा जिसमें सभी सकांय, छात्र एवं कर्मचारी इस अनूठें अवसर का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित है।

यूपी विधानसभा : प्रदेश में शराब बंदी नहीं करेगी सरकार, लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग का मुद्दा सदन में गूंजा

लखनऊ (संवाददाता) । आबकारी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं की जाएगी। शराबबंदी करने से प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी बढ़ेगी और राजस्व कम मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। विधानसभा में सपा विधायक स्वामी ओमवेश और अभय सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। स्वामी ओमवेश ने कहा कि प्रदेश में शराब बिक्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना चाहिए। ताकि युवाओं को शराब नहीं मिले। आबकारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिनियम के अनुसार आधार कार्ड केवल उन्हीं सेवाओं में अनिवार्य किया जा सकता है जिसमें सरकार सब्सिडी या सुविधाएं देती है। हालांकि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब नहीं बेची जाए। सपा विधायक अभय सिंह ने लखनऊ की समिट बिल्डिंग में संचालित बार में नाबालिग युवक युवतियों को शराब पिलाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजधानी में आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण मर्यादा शर्मशार हो रही है। उन्होंने विधायकों की एक कमेटी बनाकर समिट बिल्डिंग का निरीक्षण कराने का मुद्दा भी उठाया। आबकारी मंत्री ने कहा कि शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का उपयोग सरकार विकास योजनाओं पर करती है। शराबबंदी करने से उपभोक्ताओं को निर्धारिक मानक के अनुरूप मदिरा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इससे शराब की तस्करी बढ़ेगी। आबकारी मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय शराब माफिया नीतियां बनाते थे और सरकार चलाते थे। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अवैध शराब से एक भी मौत नहीं हुई है। अध्यक्ष जी..मेरे एक दिन डेंगू का बुखार आ गया था..मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जिनसे मेरा स्टाफ का मामला है, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने सुबह आठ बजे मुझे टेलीफोन करके मेरा हाल चाल पूछा और कहा कि इतने विशालकाय शरीर में एक मच्छर ने असर दिखा दिया। मुख्यमंत्री के पूछने का इतना असर हुआ कि डेंगू छु मंतर हो गया। डेंगू ने सोचा भागो ऐसा न हो कि बाबा का बुलडोजर मुझे भी रौंद दें। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने बृहस्पतिवार को सदन में जब यह बात कही तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। स्वामी ओमवेश ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुक्त कंठ से सीएम योगी, लोक निर्माण मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रशंसा की तो सदन में सालों के बाद इतने ठहाके गूंजे।

112 विद्यालयों ने परीक्षा केंद्रों पर जताई आपत्ति

सीतापुर (संवाददाता)। 112 कॉलेजों ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों को नकार दिया है। कॉलेजों का कहना है कि मनमाने तरीके केंद्र बने हैं। जमीनी हकीकत नहीं परखी गई। इन आपत्तियों को देखकर अफसरों ने माथापच्ची शुरू कर दी है। एक–एक कॉलेज के दावे परखे जा रहे हैं। तीन दिन के अंदर इन आपत्तियों को निस्तारित कर दिया जाएगा। जिले में 158 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 28 नवंबर तक कॉलेजों ने आपत्तियां दीं। सर्वाधिक 35 कॉलेजों ने कहा कि आखिर मेरे कॉलेज में क्या समस्या थी। पिछले साल कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। हर बार नकलविहीन परीक्षा कराई गई। इस बार परीक्षा केंद्र क्यों नहीं बनाया गया। फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया।

शाम को कार्यालयों पर सीडीओ का छापा

हरदोई (संवाददाता)। मुख्य विकास अधिकारी ने गुरुवार शाम को विकास भवन स्थित कई कार्यालयों पर छापा मारा। पांच कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के गैरहाजिर मिले। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि गैरहाजिरी के संबंध में कर्मचारियों से जवाब–तलब और कार्रवाई की जाए। सीडीओ सौम्या गुरुरानी ने कार्यालयों में अधिकारियों–कर्मचारियों की हाजिरी जांचने के उद्देश्य से शाम को जिला विकास कार्यालय, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में पहुंचीं। जिला विकास कार्यालय में कनिष्ठ सहायक मोहित दुबे, पत्र वाहक रचना सहगल गैरहाजिरी मिलीं।

बिजली उपभोक्ताओं को झटका, प्रदेश में 15 से 30 फीसदी तक महंगी हो सकती है घरेलू बिजली

लखनऊ (संवाददाता) । प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में बृहस्पतिवार को वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें 11 से 12 हजार करोड़ का गैप (घाटा) बताया गया है। अगर आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार किया कि तो 15 से 30 फीसदी तक बिजली महंगी हो सकती है। पिछली बार नौ हजार करोड़ के घाटे पर 15 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे नियामक आयोग ने खारिज कर दिया था। नया टैरिफ प्लान तैयार करने के पहले विद्युत वितरण निगमों की ओर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव दाखिल किया जाता है। फिर उसी हिसाब से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल होता है। बृहस्पतिवार शाम को नियामक आयोग में दाखिल एआरआर में करीब 11 से 12 हजार करोड़ के बीच गैप (घाटा) दिखाया गया है। यह आरडीएसएस योजना में दाखिल 13. 06 प्रतिशत लाइन हानियों के आधार पर है। इसमें एक लाख पैंतालीस हजार मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताते हुए उसकी कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ से 85,000 करोड़ के बीच में आंकी गई है। इसके पहले वर्ष 2023–24 में लगभग 92,547 करोड़ का वार्षिक राज्य आवश्यकता दाखिल की गई थी। तब बढ़ोतरी की दर 15 से 25 फीसदी आंकी गई थी। इस बार एआरआर दाखिल करते समय बढ़ोतरी की जिम्मेदारी नियामक आयोग पर छोड़ दी गई है। मामले में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33,122 करोड़ बकाया है। वर्ष 2024–25 में निगमों की ओर से करीब 11 से 12 करोड़ के बीच गैप (घाटा) विद्युत नियामक आयोग से बिजली दरों में बढ़ोतरी की साजिश है। इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा।

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

लखनऊ (संवाददाता) । घर के बाहर खेल रही पड़ोसी की पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी गिरधारी अग्रहरि को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के चिकित्सीय और मानसिक आघात की पूर्ति व उसके पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील अनुपमा श्रीवास्तव और विनय कुमार ने बताया कि वादी ने आशियाना थाने में 17 जनवरी 2021 में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि शाम साढ़े सात बजे उसकी पांच वर्ष की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी रामबृज गुप्ता के मकान की रखवाली करने वाला गिरधारी अग्रहरि बुरी नीयत से उसे पकड़कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद मासूम रोती हुई घर आई और अपनी मां को सारी बात बताई।

पान मसाला और तंबाकू की दो फर्मों पर राज्य कर का छापा, 1.23 करोड़ रुपये जमा कराए गए

लखनऊ (संवाददाता) । पान मसाला और तंबाकू का कारोबार करने वाली दो ट्रेडिंग फर्मों पर राज्यकर विभाग की विशेष अनुसंधान इकाई ने छापा मारकर करोड़ों की अनियमितताएं पकड़ीं। जांच के दौरान कर चोरी का खुलासा होने पर 1.23 करोड़ रुपये जमा कराए गए। राज्य कर आयुक्त ने पूरे प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू बनाने वाली फर्मों पर जांच के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड–1 जोन प्रथम डीपी सिंह ने पान मसाले की दो फर्मों द्वारा दाखिल किए जा रहे विवरणों का परीक्षण विभागीय आईटी टूल व पोर्टल डाटा से किया। फर्म के जीएसटीआर–टूए, टूबी और ई वे बिल इनवर्ड की जांच से पता चला कि फर्म ने इनवर्ड रॉ मैटेरियल, सुपाड़ी और पैकिंग मैटेरियल की तुलना में उत्पादन को कम करके प्रदर्शित किया है। इसके द्वारा टर्नओवर को कम प्रदर्शित करते हुए टैक्स चोरी की जा रही है। इस आधार पर अपर आयुक्त प्रकाश यादव, संयुक्त आयुक्त अरुण शंकर राय ने फर्म द्वारा दाखिल रिटर्न का विस्तृत परीक्षण कर उत्पादन और टर्नओवर में व्यापक खामियां पाईं। इसके बाद एसआईबी की टीमों ने फर्म के कारोबारी दफ्तर में छापा मारा। वरिष्ठ अधिकारियों की पांच टीमों ने छापों में हिस्सा लिया।। इस दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा विभिन्न कंपनियों से सुपाड़ी, कत्था, पैकिंग मैटेरियल, मेंथा आयल आदि की खलीद की जा रही थी।

बाइक की टक्कर से किसान की मौत

हरदोई (संवाददाता)। क्षेत्र के समजलपुर गांव में मकान के बाहर खड़े बुजुर्ग किसान को बुधवार रात तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।समजलपुर निवासी देवी प्रसाद (60) खेती करते थे। बुधवार की रात वह अपने मकान के बाहर खड़े थे। इसी बीच एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आया और उन्हें टक्कर मारते हुए भाग निकला। शोर सुनकर देवी प्रसाद के परिजन बाहर आ गए। उन्हें सीएचसी सांडी ले गए।

32 हजार संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ा वेतन लागू, 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा

लखनऊ (संवाददाता) । परिवहन निगम के संविदा ड्राइवर व कंडक्टरों को बढ़ा हुआ वेतन पहली दिसम्बर से लागू कर दिया जाएगा। इससे लखनऊ में करीब तीन हजार सहित प्रदेशभर में तैनात 32 हजार कर्मियों को राहत हो जाएगी। वर्तमान में जो पारिश्रमिक में प्रति किमी. मिल रहा है, उसमें 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा। इस सम्बंध में रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी किया है। यह जानकारी रोडवेज के प्रधान प्रबंधक(कार्मिक) अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि रोडवेज में कार्यरत ड्राइवरों–कंडक्टरों का पारिश्रमिक दरों को रिवाइज किया गया है। अभी तक 1.75 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 1.89 रूपये प्रति किमी. कर दिया गया है। नई दर से देय भुगतान एक दिसंबर से लागू होगा। इससे संविदा चालक परिचालकों को 750 रुपये से तीन हजार रुपये तक प्रतिमाह का लाभ होगा। रोडवेज बसों में आग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दस उपाय तैयार किए गए हैं। जिनके जरिए बसों की गहन पड़ताल के साथ ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेशभर के 115 बस वर्कशॉप व 20 क्षेत्रीय डिपो में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। रोडवेज के जनसम्पर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह जांच सेवा प्रबंधक के नेतृत्व में होगी। प्रतिमाह अनुबन्धित बसों को संबंधित डिपो कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में चेकिंग के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक होंगे।

शहीद पथ पर हादसे में एफसीआई कर्मचारी की मौत

लखनऊ (संवाददाता) । शादी से घर लौट रहे एफसीआई कर्मचारी को बुधवार देर रात पीजीआई इलाके में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं, मड़ियांव व चिनहट इलाकों में भी सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। आलमबाग के आजादनगर निवासी अनुभव (28) गोंडा एफसीआई में कार्यरत थे। बीते बुधवार रात वह एक दोस्त की शादी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गए थे। रात डेढ़ बजे लौटते समय पीजीआई इलाके में उतरेठिया के पास शहीद पथ पर उनकी स्कूटी में तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। वाहन से कुचलकर अनुभव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने अनुभव को अपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पास मिले सामान की मदद से पुलिस ने पहचान कर परिजनों को खबर देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनुभव परिवार के इकलौते बेटे थे।

यूपी विधानसभा : अयोध्या तीर्थ विकास परिषद समेत पांच विधेयक पारित, तीन नए सरकारी विवि खुलने का रास्ता साफ

लखनऊ (संवाददाता) । प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही प्रमुख तीर्थस्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा तीन तीर्थ विकास परिषदों के गठन से संबंधित विधेयकों समेत कुल पांच विधेयकों को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। इसमें उप्र श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के साथ ही उप्र श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और उप्र श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 शामिल है। इसके अलावा उप्र निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 और उप्र राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने बीते दिनों अयोध्या में हुई कैबिनेट में तीनों तीर्थ विकास परिषदों को गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसे कानून जामा पहनाने के लिए सरकार विधेयक लेकर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया। हालांकि सपा समेत अन्य विपक्षी दल इन विधेयकों में कई संशोधन पेश किया और इसमें स्थानीय विधायक व सांसद को भी सदस्य बनाने की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की बात कही, जिसे सरकार के स्पष्टीकरण के बाद अस्वीकार करते हुए सभी विधेयकों को पारित कर दिया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सदन में कहा कि सरकार तीनों तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक और स्थापत्य संबंधी विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से ही इन तीर्थ विकास परिषदों का गठन करने का फैसला किया है। ये तीर्थ विकास परिषद एक निगमित निकाय होगी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, पर्यटन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश सरकार करेगी। इसके सदस्य व सह–संयोजक प्रमुख सचिव पर्यटन होंगे। उन्होंने बताया कि आवास एवं नगर नियोजन, वित्त, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, नगर विकास, परिवहन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। संबंधित मंडलायुक्त, डीएम समेत मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त पदेन सदस्य होंगे। इनके अलावा आवास एवं नगर नियोजन, वित्त, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, नगर विकास, परिवहन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव भी सदस्य होंगे। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का दान देने वाले दानदाता को भी परिषद का सदस्य बनाया जा सकेगा। इसमें एक नियोजन तथा विकास समिति भी गठित की जाएगी।

बूंदाबादी ने बढ़ाई सर्दी, तापमान एक डिग्री गिरा

हरदोई (संवाददाता)। सुबह बूंदाबादी से हुई और आसमान में घने बादल छाए रहे। इससे सर्दी बढ़ गई, तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सर्दी बढ़ने के साथ ही बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार की सुबह आसमान में घने बादल छा गए। कुछ देर हल्की बूंदाबादी हुई। दिन में 11 बजे के बाद मौसम साफ हुआ। पूरे दिन चार किमी की रफ्तार से पुरवा हवा चलती रही। इससे सर्दी बढ़ गई। सर्दी बढ़ने के साथ ही बाजार गर्म कपड़ों से सज गए है।

गोरक्षनगरी में निवेश के लिए आ रहे उद्यमी

हरदोई (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले लोग यूपी में उद्योग लगाने से कतराते थे। अब गोरक्षनगरी में निवेश के लिए उद्यमी आगे आ रहे हैं। पहले यहां के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे। अब बाहर के अच्छे लोग रोजगार की तलाश में गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर बदल रहा है। सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को गीडा के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया।

पांच मिमी बारिश से छह डिग्री गिरा दिन का पारा, आलू, मटर और गेहूं की फसल पर मंडराया खतरा

लखनऊ (संवाददाता) । बादल–बारिश और हवा बढ़ती सर्दी का अहसास करा रही है। बुधवार को देर रात शुरु हुई कभी तेज तो कभी धीमी बरसात का सिलसिला बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। इस बीच हवा चलती रही, कोहरा भी छाया रहा। ये सभी परिस्थितियां ठंड के अनुकूल रहीं, इसके कारण तापमान में 6 डिग्री के करीब गिरावट आई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, शुक्रवार से ही ठंड और बढ़ेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र में पांच मिमी के करीब बरसात रिकार्ड हुई। हवा की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सामान्य से थोड़ी तेज जरूर रही। कोहरा भी छाया रहा और सुबह से शाम तक बादलों ने डेरा डाले रखा। दिन में 11 बजे के आसपास धूप की झलक दिखी जरूर पर चंद सेकेंड के लिए ही। आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र में दिन का तापमान 22.1 डिग्री रहा, जो एक दिन पहले के 27.8 के मुकाबले 5. 7 डिग्री कम रहा। रात के पारे में एक डिग्री की बढ़ोतरी रही, ये 15 डिग्री की अपेक्षा 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, दो दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। इसके बाद पारा और गिरना शुरू होगा। बृहस्पतिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले बीते सोमवार को पारा 23.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। आलू की फसल को नमी के कारण नुकसान होगा। यदि यह स्थिति एक सप्ताह से ज्यादा बनी रही तो इसका असर आलू की फसल पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह के मुताबिक, यदि नमी बढ़ती है तो आलू में अगेती झुलसा तेजी से फैलता है।

यह पानी फूलगोभी की फसल को नुकसान पहुंचाएगा, उसमें कीड़ा लगने लगेगा। इसके अलावा हरी मटर की फसल के लिए भी मौसम का ये बदलाव घातक है। बख्शी का तालाब के किसान महिपाल, रामधार, जयकरण सिंह का कहना है।

कमरे में मृत मिला मंडी परिषद कर्मचारी, हत्या की आशंका

लखनऊ (संवाददाता) । विभूतिखंड स्थित मंडी परिषद कॉलोनी में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव संदिग्ध हालात में उसके कमरे में पड़ा मिला। मुंह व नाक से खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट से मौत की पुष्टि हुई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पीजीआई के वृंदावन सेक्टर पांच निवासी पवन कुमार (30) विभूतिखंड स्थित मंडी परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। वह मंडी परिषद कॉलोनी में ही आवंटित मकान में रहते थे। बुधवार रात पड़ोसियों को उनके कमरे से बदबू का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पवन के कमरे का दरवाजा चिपका था। पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो कमरे में फर्श पर पवन का शव पड़ा मिला।

विधानसभा सत्र : आवारा पशुओं ने ली 17 लोगों की जान, यूपी को हर साल मिल रहे हैं 3258 डॉक्टर

लखनऊ (संवाददाता) । निराश्रित गोवंश से इस वर्ष अब तक गोरखपुर व प्रयागराज मंडल में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जबकि लखनऊ मंडल में 17 लोगों की जान गई है। इसमें लखीमपुर खीरी के आठ, सीतापुर के पांच और हरदोई के चार लोग शामिल हैं। इनमें से 16 लोगों के परिजनों को चार–चार लाख रुपये की मदद दी गई है। सीतापुर में एक व्यक्ति के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उन्हें मदद नहीं दी गई। यह जानकारी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान परिषद में एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि पशुओं से दुर्घटना न हो, इसके लिए निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए एक नवंबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में हर साल 3258 विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। इससे न सिर्फ इलाज सुगम होगा बल्कि हर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त चिकित्सा शिक्षक भी होंगे।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।